

एचपीसीएल ने 10 डिस्ट्रीब्यूटर को किया निलंबित

नई दिल्ली, 03 अप्रैल. एलपीजी वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एचपीसीएल ने बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने अनियमितताओं में शामिल पाए गए 10 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर को सस्पेंड कर दिया है. यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब सरकार गैस आपूर्ति को लेकर अफवाहों, जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती बरत रही है. एचपीसीएल ने साफ किया है कि वह अपने वितरण नेटवर्क में किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा और 'जीरो-टॉलरेंस' नीति के तहत दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. इधर, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी राज्यों और केंद्र

एलपीजी अनियमितता पर एचपीसीएल की बड़ी कार्रवाई



शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि वे गैस की उपलब्धता को लेकर सही जानकारी समय-समय पर जनता तक पहुंचाएं. सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों के कारण कई जगहों पर घबराहट में खरीदारी देखी गई है. सरकार और कंपनियों के इस

संयुक्त एक्शन का उद्देश्य उपभोक्ताओं का भरोसा बनाए रखना और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू रखना है. एलपीजी वितरण में अनियमितताओं को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए (एचपीसीएल) ने 10 डिस्ट्रीब्यूटर को सस्पेंड कर दिया है. कंपनी ने

स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई उसके 'जीरो-टॉलरेंस' नीति के तहत की गई है, जिसके तहत ग्राहक हितों और पारदर्शिता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. एचपीसीएल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए बताया कि जिन डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ शिकायतें और अनियमितताओं के प्रमाण मिले, उनके खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई. कंपनी का कहना है कि वह अपने नेटवर्क में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं.

6 साल में 12 सिलेंडर ही मिलेंगे

भारत में एलपीजी गैस ने रसोई की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है. प्रधान मंत्री उज्वला योजना जैसी योजनाओं के चलते अब गांव से लेकर शहर तक लगभग हर घर में गैस सिलेंडर पहुंच चुका है। इससे खाना बनाना आसान हुआ है और महिलाओं के जीवन स्तर में भी बड़ा सुधार आया है। लेकिन जैसे-जैसे गैस उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है, वैसे-वैसे इसके नियमों में भी बदलाव किए गए हैं. आज हर उपभोक्ता के लिए यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि वह एक साल में कितने सिलेंडर सब्सिडी पर ले सकता है और उसकी सीमा क्या है.

गोल्ड रेट में बड़ी गिरावट, निवेशकों को राहत

3500 रुपए नीचे आया सोना



नई दिल्ली, 03 अप्रैल. गुड फ्राइडे के मौके पर देश में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, जिससे खरीदारों और निवेशकों को राहत मिली है. पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद आज बाजार में नरमी का रुख नजर आया है. राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव घटकर 1,49,110 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 1,48,960 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है. यह गिरावट ऐसे समय में आई है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक संकेतों और मुद्रा विनिमय दर में

बदलाव का असर घरेलू बाजार पर पड़ा है. इससे सोने की कीमतों में कमी आई है, जो उपभोक्ताओं के लिए खरीद का अच्छा अवसर बन सकता है. देश में सोने की कीमतों में आज गिरावट दर्ज की गई है, जिससे बाजार में देखी जा रही है. गुड फ्राइडे के दिन आई इस गिरावट ने खरीदारों को कुछ राहत दी है. राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर 1,49,110 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. वहीं मुंबई में भी सोने का भाव गिरकर 1,48,960 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. इससे पहले दिल्ली के सरफा बाजार में सोने की कीमत में करीब 3,500 रुपये यानी 2.26 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ताजा आंकड़ों के अनुसार, हाजिर सोने का भाव 4,591.52 डॉलर प्रति औंस के आसपास बना हुआ है. वैश्विक स्तर पर डॉलर की चाल, ब्याज दरों की स्थिति और निवेशकों की मांग जैसे कारक सोने की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में नरमी आती है या मुद्रा मजबूत होती है, तो उसका सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ता है. भारत जैसे देश, जो सोने का बड़ा आयातक है, वहां कीमतें वैश्विक संकेतों के अनुसार तेजी से बदलती हैं.

विदेशी मुद्रा भंडार में 10.28 बिलियन डॉलर की गिरावट

नई दिल्ली, 3 अप्रैल भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) एक बार फिर गिरावट के दौर में है. भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 27 मार्च तक देश का कुल फॉरेक्स रिजर्व 688.05 बिलियन पर आ गया, जो पिछले सप्ताह 10.28 बिलियन की कमी को दर्शाता है. इससे पहले, पिछले सप्ताह में भी कुल भंडार में 11.413 बिलियन की गिरावट देखी गई थी. यह लगातार गिरावट पश्चिम एशिया संघर्ष और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं का परिणाम है. फॉरेक्स रिजर्व में मुख्य घटक विदेशी मुद्रा संर्पत्ति में 6.622 बिलियन की गिरावट आई और यह 551.072 बिलियन पर आ गई.

इसमें डॉलर, यूरो, पाउंड और येन जैसी मुद्राओं का प्रभाव शामिल है. यही वजह है कि वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव सीधे भारत के फॉरेक्स रिजर्व को प्रभावित कर रहे हैं. यह लगातार गिरावट यह संकेत देती है कि वैश्विक संकट और निर्यात-आयात असंतुलन देश के भंडार पर दबाव डाल रहे हैं. फरवरी में फॉरेक्स रिजर्व 728.494 बिलियन के उच्चतम स्तर पर थे, लेकिन वेस्ट एशिया संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव ने इसे कम कर दिया. विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी मुद्रा भंडार में स्थिरता बनाए रखना और निर्यात को बढ़ावा देना भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी है.

सेल के चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश का इस्तीफा

केके सिंह ने सेल के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाला

नई दिल्ली, 02 अप्रैल। सेल के निदेशक (कार्मिक) कृष्ण कुमार सिंह ने गुरुवार को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया. श्री सिंह के पास प्रचालन, मानव संसाधन विकास, सतर्कता और कार्मिक एवं प्रशासन जैसे विविध क्षेत्रों में लगभग चार दशकों का गहन अनुभव है.



तक अपना योगदान दिया. उन्होंने कार्मिक और प्रशासन विभाग के कार्यकारी निदेशक (प्रभारी)

सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है. श्री सिंह को 2022 में निदेशक (कार्मिक) नियुक्त किया गया, जो इस क्षेत्र के बारे में उनके गहरे ज्ञान और मजबूत नेतृत्व कौशल को दर्शाता है. इस भूमिका में उन्होंने सेल के मानव संसाधन के कार्यालय का नेतृत्व किया है. उन्होंने कार्यबल को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु विकासशील कार्मिक कल्याण और विकास योजनाओं की शुरुआत की है.

सेल ने 2025-26 में बिक्री, उत्पादन में बनाये नये रिकॉर्ड

सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने वित्त वर्ष 2025-26 में बिक्री और उत्पादन दोनों में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है. पूरे वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने 201.4 लाख टन की अब तक की सर्वाधिक बिक्री दर्ज की जो एक साल पहले के 180.7 लाख टन की तुलना में 11.5 प्रतिशत अधिक है.

इंजन के निर्माण में 25% तक ऊर्जा की बचत

नई दिल्ली, 03 अप्रैल. भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया कीर्तिमान जुड़ गया है. (सीएलडब्ल्यू) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का उत्पादन कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है. 76 साल पहले एक छोटे से वर्कशॉप के रूप में शुरू हुआ यह संस्थान आज दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माण इकाई बन चुका है. करीब 8,000 से अधिक कर्मचारियों के साथ यह युनिट हर लोकोमोटिव के निर्माण में 25 प्रतिशत तक ऊर्जा की बचत करने में भी सफल रही है. पेपरलेस वर्किंग और डिजिटल



प्लेटफॉर्म अपनाकर सीएलडब्ल्यू ने खुद को एक 'स्मार्ट फैक्ट्री' के रूप में स्थापित किया है. आज यह न केवल भारतीय रेलवे का पावरहाउस है, बल्कि वैश्विक स्तर पर इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का प्रतीक बन चुका है.

इस उपलब्धि के साथ सीएलडब्ल्यू ने न केवल भारत की तकनीकी क्षमता को दुनिया के सामने रखा है, बल्कि अमेरिका और यूरोप की बड़ी कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया है. यह सफलता 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है. भारतीय रेलवे के लिए 31 मार्च 2026 की तारीख ऐतिहासिक बन गई, जब न एक ही वित्तीय वर्ष में 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का उत्पादन कर विश्व रिकॉर्ड कायम किया.

पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल महंगा

नई दिल्ली, पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है. पेट्रोल अब 458.41 और डीजल 520.35 पाक रुपये प्रति लीटर हो गया है. केरोसिन की कीमत 457.80 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दी गई है. सरकार ने पेट्रोल में 43 और हाई-स्पीड डीजल में 55 प्रतिशत का इजाफा किया है. अमेरिकी-ईरान युद्ध और होमजुज रुट पर तनाव के चलते ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का असर यहां देखा गया है. कीमतों में बढ़ोतरी को संतुलित करने पेट्रोल पर टैक्स 105 रुपये से बढ़ाकर 160 रुपये प्रति लीटर किया गया.

कुकिंग गैस पर निर्भरता घटाने की तैयारी

सरकार घरेलू इंडक्शन हीटर उत्पादन बढ़ाने पर कर रही फोकस

नई दिल्ली, 03 मार्च. केंद्र सरकार कुकिंग गैस की खपत कम करने के लिए अब इंडक्शन हीटर और उससे जुड़े उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की योजना बना रही है. इस दिशा में शुक्रवार को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव, विद्युत सचिव और विदेश व्यापार (डीजीएफटी) के महानिदेशक सहित शीर्ष अधिकारियों ने एक उच्चस्तरीय बैठक की. इस बैठक

खासतौर पर तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के आयात में बाधा को लेकर चिंता जताई जा रही है. सरकार पहले ही कई पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर आयात शुल्क कम कर चुकी है, ताकि सलाई बनी रहे और लागत का दबाव कम किया जा सके.

ताकि कुकिंग गैस की खपत कम की जा सके. पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद से इंडक्शन हीटर और अन्य इलेक्ट्रिक उत्पादों की मांग में काफी बढ़ोतरी देखी गई है. एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, अगर यह युद्ध लंबे समय तक चलता है, तो भारत को संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा. यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब सरकार लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की संभावना को देखते हुए आयात पर पड़ने वाले असर का आकलन कर रही है.

समाचार विशेष

सीपीआई, कांग्रेस और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला

तिरुवनंतपुरम. केरल की त्रिश्य विधानसभा सीट इस बार राज्य की सबसे चर्चित और हॉट सीटों में से एक है. इस सीट में सत्तारूढ़ वाम मोर्चा (एलडीएफ), कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ और भाजपा के बीच सीधी त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है. वामपंथी खेमे ने अलंकोडे लीलाकृष्णन को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने राजन पल्लव पर दांव खेला है. वहीं, भाजपा ने इस सीट

है. त्रिशूर विधानसभा सीट पर नायर, एल्लावा और ईसाई समुदाय के वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं. सत्तारूढ़ वाम मोर्चा एलडीएफ को पारंपरिक वामपंथी वोट बैंक और मजदूर वर्ग का समर्थन मिलता है. यूडीएफ को ईसाई और अल्पसंख्यक वोटों का मजबूत

आधार माना जाता है. भाजपा इस बार हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण और शहरी वोटर्स को साधने की कोशिश में है. 2021 विधानसभा

को प्रतिष्ठा का सवाल बनाते हुए पञ्चाय वेणुगोपाल को उम्मीदवार बनाया है, जो कि महिला हैं. त्रिशूर को केरल की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है. यहां शहरी, मध्यवर्गीय और परंपरागत मतदाताओं का मिला-जुला प्रभाव है. यही वजह है कि यहां हर चुनाव में मुकाबला कड़ा रहता है. इस बार भाजपा ने भी पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया

चुनाव के परिणाम की बात करें तो यहां से सीपीआई के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी. सीपीआई के पी. बालचंद्रन ने मात्र 946 वोटों (0.74 प्रतिशत) के अंतर से जीत हासिल की थी. कांग्रेस उम्मीदवार पञ्चाय वेणुगोपाल 43,317 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहें थीं. भाजपा के सुरेश गोपी 40,457 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे. अब स्थिति और पेचीदा हो गई है. बालचंद्रन मैदान में नहीं हैं.

क्या है ग्रांड रिपोर्ट ?

त्रिशूर में मुकाबला बेहद कटौत का माना जा रहा है. एलडीएफ अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, जबकि कांग्रेस बापसी की कोशिश में है. भाजपा यहां अपने वोट शेयर को बढ़ाकर चौकाने की रणनीति पर काम कर रही है. कुल मिलाकर, त्रिशूर सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला चुनावी नतीजों को दिलचस्प बना सकता है और यह सीट केरत की राजनीति का रुख तय करने वाली साबित हो सकती है.

किधर जाएगा मुस्लिम वोटर एलडीएफ या यूडीएफ ?

विजयन को सत्ता से हटाने बीजेपी का भी एड़ी-चोटी का जोर

तिरुवनंतपुरम. केरल विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर किस तरफ जाएंगे, इसमें भाजपा एक बड़ा फैक्टर बनती दिख रही है. राज्य में 9 अप्रैल को वोटिंग है और एलडीएफ व यूडीएफ - दोनों ही अल्पसंख्यकों का वोट पाने की कोशिश में हैं.



जिस तरह दोनों गठबंधनों के नेता एक-दूसरे पर भाजपा की बी-टीम होने का आरोप लगा रहे हैं, उससे साफ है कि दोनों को पता है कि मुस्लिम वोटर्स की दिशा तय करने में भाजपा एक अहम फैक्टर है. केरल में ऐसा पहले भी होता

रहा है. 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ज्यादातर लोगों को चिंता थी कि कहीं राज्य का सांप्रदायिक सौहार्द खराब ना हो. अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए तब भी भाजपा बड़ा फैक्टर थी और उसके

खिलाफ उन्हें यूडीएफ ही मजबूत लगी. तब जनता में सरकार को लेकर नाराजगी भी थी. नतीजे आए तो 20 लोकसभा सीटों में से 18 पर यूडीएफ उम्मीदवारों को जीत मिली थी.

हर फॉर्मूला आजमाएंगे एमके स्टालिन

चेन्नई. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन चुनाव जीतने के लिए हर फॉर्मूला आजमाएंगे.

बिहार या झारखंड जैसे गरीब और पिछड़े राज्यों में जो फॉर्मूले आजमाए गए थे और चुनाव जीते गए थे वो सब स्टालिन भी आजमा रहे हैं. उन्होंने अपनी पार्टी का चुनाव घोषणापत्र जारी किया तो उसमें कहा कि सरकार बनी तो उनकी सरकार हर परिवार की महिला मुखिया को आठ हजार रुपए का एक कूपन देगी, जिससे वे फ्रीज, वॉशिंग मशीन या घर का कोई दूसरा इलेक्ट्रिक सामान खरीद सकेगी. यह बिहार का फॉर्मूला है. जहां चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपए डाले गए, कहा गया कि इससे वे बिजनेस का कोई प्रस्ताव तैयार करें और सरकार को दें. दोनों में थोड़ा फर्क है लेकिन महिलाओं को एकमुश्त राशि देने का आइडिया एक जैसा है. इसी तरह झारखंड ने और दूसरे कई राज्यों ने, जिनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्य भी शामिल हैं. उन्होंने महिलाओं को सम्मान राशि देने का ऐलान किया या देना शुरू किया. तमिलनाडु में महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए मिलते हैं, जिसे स्टालिन ने बढ़ाने का ऐलान किया है.

विशेष भाजपा ने वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह, तृणमूल ने युवा नेता त्रिणांकुर भट्टाचार्य को उतारा

नोआपाड़ा में अनुभव बनाम युवा चेहरा

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की अहम सीटों में शुमार नोआपाड़ा में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है. औद्योगिक इतिहास, घनी आबादी, प्रवासी प्रभाव और बदलते राजनीतिक समीकरणों की वजह से यह सीट एक बार फिर राज्य की राजनीति का केंद्र बन गई है. इस बार यहां मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर के रूप में उभर रहा है.

बीजेपी ने इस सीट से वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जो पहली बार नोआपाड़ा से चुनाव मैदान में उतरे हैं. हालांकि, वह अपने चार दशक के राजनीतिक अनुभव को अपनी सबसे बड़ी ताकत बता रहे हैं. अर्जुन सिंह का कहना है कि क्षेत्र उनका नहीं है और उन्होंने लंबे समय तक आसपास के इलाकों में सक्रिय

राजनीति की है. उनका दावा है कि इस बार मुकाबला एकतरफा है और इसे 80-20 की लड़ाई बताया जा सकता है. उनके मुताबिक, 80 प्रतिशत समर्थन बीजेपी के पक्ष में है, जबकि बाकी वोट विपक्षी दलों, तृणमूल, वाम और कांग्रेस में बंटे हुए हैं. बीजेपी उम्मीदवार ने दावा किया कि हाल के

समय में बड़ी संख्या में ऐसे नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जिन्हें डुफ्टीकेट या मूट मतदाता माना गया. उनका कहना है कि इससे चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और कथित फर्जी मतदान की संभावना कम होगी. घर का लड़का बनकर अपील - दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस ने इस सीट से युवा नेता त्रिणांकुर भट्टाचार्य को उम्मीदवार बनाया है. वह खुद को इलाके का बेटा बताते हुए जनता से भावनात्मक जुड़ाव पर जोर दे रहे हैं. त्रिणांकुर का

इस बार मुकाबला दिलचस्प

कोलकाता महानगर क्षेत्र से सटे नोआपाड़ा की पहचान एक घनी आबादी वाले शहरी-उपनगरीय इलाके के रूप में है. यहां मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग की बड़ी आबादी रहती है, जहां रोजगार, बुनियादी सुविधाएं और विकास जैसे मुद्दे चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं. नोआपाड़ा में इस बार मुकाबला दिलचस्प होने के साथ-साथ बेहद अहम भी है. एक तरफ बीजेपी का अनुभवी चेहरा है, तो दूसरी ओर तृणमूल का युवा नेतृत्व. राजनीतिक दावे और आरोप-प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन अंतिम फैसला मतदाताओं को करना है कि वे अनुभव पर भरोसा करते हैं या नए नेतृत्व पर. अब नजरे इस बात पर टिकी हैं कि नोआपाड़ा की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है.

कहा गया कि इससे वे बिजनेस का कोई प्रस्ताव तैयार करें और सरकार को दें. दोनों में थोड़ा फर्क है लेकिन महिलाओं को एकमुश्त राशि देने का आइडिया एक जैसा है. इसी तरह झारखंड ने और दूसरे कई राज्यों ने, जिनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्य भी शामिल हैं. उन्होंने महिलाओं को सम्मान राशि देने का ऐलान किया या देना शुरू किया. तमिलनाडु में महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए मिलते हैं, जिसे स्टालिन ने बढ़ाने का ऐलान किया है.

